STATESMAN, Delhi, 4.3.2025
Page No. 3, Size:(24.90)cms X (13.02)cms.

6-day capacity building programme for rights bodies of Global South begins

STATESMAN NEWS SERVICE
NEW DELHI, 3 MARCH

The Indian Technical and Economic Cooperation Executive (ITEC) capacity building programme for the National Human Rights Institutions (NHRIs) from Global South got underway here on Monday.

The six-day programme is being organised by the National Human Rights Commission (NHRC) in collaboration with the Ministry of External Affairs (MEA).

The programme is being attended by 47 delegates from the NHRIs of 14 countries from the Global South. The participating countries include Madagascar, Uganda, Samoa, Timor Leste, DR Congo, Togo, Mali, Nigeria, Egypt, Tanzania, Mauritius, Burundi, Turkmenistan, and Qatar, as per the NHRC.

In his inaugural address, NHRC Chairperson Justice V Ramasubramanian said India is a country of rich and diverse cultural ethos with various castes, communities, art forms, and languages, yet thrives in its unity of shared values and traditions for centuries.

However, he said diversity also comes with diverse problems requiring diverse solutions. "Every country has its socio-cultural, political, and economic traditions and diversities may face challenges while addressing the human rights issues given their standardised approaches set to dealing with them following the Universal Declaration of Human Rights. Therefore, solutions to the problems can't be tailor-made for every country to follow," the Chairperson said.

Ramasubramanian also referred to many ancient Indian texts highlighting the human values and ethos practiced in the countries or centuries, which hold relevance even today for the whole world.

NHRC Secretary General Bharat Lal said India traditionally wanted to share its most cherished knowledge and wisdom for the larger cause of humanity. This training has been organised with the same spirit wherein we hope and expect to learn from each other.

He expressed his gratitude to the participating senior functionaries of the NHRIs of Global South and their countries for accepting NHRC's invitation to depute them for participation.

A NHRC member. Justice Bidyut Ranjan Sarangi, said the commission has played a crucial role in shaping India's human landscape through its wide-ranging initiatives. "Unlike many Western approaches that emphasise individual freedom above all else, India follows a more balanced model that values both individual and collective rights. India's engagement in international human rights forums reflects its dedication to building a just and equitable global order," Sarangi elaborated.

He said that capacity-building initiatives like ITEC play a crucial role in expanding our knowledge and refining our skills.

Vijaya Bharathi Sayani, who is also a member of the rights body, said by sharing our collective wisdom and resources, we can significantly enhance the protection and promotion of human rights across our nations and regions in the scenario of constantly evolving global human rights landscape.

She also highlighted some of the key thematic issues of human rights that are being focused on by the NHRC including the rights of women and achieving gender equality, protecting marginalised communities, safeguarding vulnerable populations in the context of development and displacement, among others.

NHRC Secretary General Bharat Lal said India traditionally wanted to share its most cherished knowledge and wisdom for the larger cause of humanity. This training has been organised with the same spirit wherein we hope and expect to learn from each other.

Senior officers of the NHRC and the MEA were present on the occasion.

NHRC NIC

एनएचआरसी, भारत का विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ग्लोबल साउथ के एनएचआरआई के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर केन्द्रित आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नई दिल्ली में शुभारंभ

https://nhrc.nic.in/media/press-release/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%9D%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A5-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली: 3 मार्च, 2025

एनएचआरसी, भारत का विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ग्लोबल साउथ के एनएचआरआई के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर केन्द्रित आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नई दिल्ली में शुभारंभ

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी.रामासुब्रमण्यन ने भारत की समृद्ध विविध सांस्कृतिक लोकाचार जिसमें विभिन्न जातियाँ, समुदाय, कला के विविध रूपों और भाषाएँ एवं सदियों से इसकी एकता को बांधने वाले साझा मूल्य शामिल हैं, पर प्रकाश डाला

उन्होंने कहा, हर देश में अपने स्वयं के विविध सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं के साथ मानव अधिकार समस्याओं को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के तहत अनुकूलित समाधान नहीं हो सकते

आईटीईसी जैसे मंच एक-दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और मानव अधिकार मूल्यों को साझा करने और आदान-प्रदान करने, लगातार उभरती मानव अधिकार चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान खोजने और सोचने का अवसर प्रदान करते हैं

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ साझेदारी में ग्लोबल साउथ के एनएचआरआई के लिए मानव अधिकारों पर छह दिवसीय भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी (आईटीईसी) क्षमता निर्माण कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में ग्लोबल साउथ के 14 देशों के एनएचआरआई के लगभग 47 प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इनमें मेडागास्कर, युगांडा, समोआ, तिमोर लेस्ते, डीआर कांगो, टोगो, माली, नाइजीरिया, मिस्र, तंजानिया, मॉरीशस, बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान और कतर देश के प्रतिभागी शामिल हैं।

न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत विभिन्न जातियों, समुदायों, कला के विविध रूपों एवं भाषाओं के साथ समृद्ध विविध सांस्कृतिक लोकाचार का देश है और फिर भी यह सदियों से साझा मूल्यों और परंपराओं की एकता में संवर्ध हो रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विविधता के साथ-साथ विविध समस्याएं भी आती हैं जिनके लिए विविध समाधानों की आवश्यकता होती है। हर देश की अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परंपराएं होती हैं और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद उनसे निपटने के लिए निर्धारित मानकीकृत दृष्टिकोणों को देखते हुए विविधताओं को मानव अधिकार मुद्दों का समाधान करते हुए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, समस्याओं का समाधान हर देश के तदनुकूल नहीं हो सकते।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि आईटीईसी जैसे मंच एक-दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और मानव अधिकार मूल्यों को साझा करने और आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि प्रत्येक देश में अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के साथ उभरती मानव अधिकार चुनौतियों का सर्वोत्तम तरीके से समाधान करने के तरीकों पर विचार और संभावनाओं की खोज की जा सके।

उन्होंने ग्लोबल साउथ के एनएचआरआई और उनके देशों के भाग लेने वाले वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने एनएचआरसी, भारत द्वारा उन्हें भागीदारी के लिए नियुक्त करने के निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का भी उल्लेख किया, जो देशों या सदियों में प्रचलित मानवीय मूल्यों और लोकाचारों पर प्रकाश डालते हैं, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं।

न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी, सदस्या, एनएचआरसी, भारत ने अपने भाषण में कहा कि आयोग ने अपनी व्यापक पहलों के माध्यम से भारत के मानव परिदृश्य को स्वरुप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमी दृष्टिकोणों के विपरीत, आयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हर चीज से ऊपर रखता है, भारत एक संतुलित मॉडल का पालन करता है जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों अधिकारों को महत्व देता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मंचों में भारत की भागीदारी एक न्यायसंगत और समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आईटीईसी जैसी क्षमता निर्माण पहल हमारे ज्ञान के विस्तार और हमारे कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए, आइए हम सम्मान, न्याय और समानता के सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहते हुए, अपनी राष्ट्रीय वास्तविकताओं के भीतर मानव अधिकार सिद्धांतों को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता को पहचानें।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि अपने सामूहिक अनुभव और स्रोतों को साझा करके, हम लगातार विकसित हो रहे वैश्विक मानव अधिकार परिदृश्य में अपने राष्ट्रों और क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मानव अधिकारों के कुछ प्रमुख

विषयगत मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिन पर एनएचआरसी, भारत द्वारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता प्राप्त करना, हाशिए पर रहे समुदायों की सुरक्षा, विकास और विस्थापन के संदर्भ में सुभेद्य आबादी की सुरक्षा आदि शामिल हैं।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत पारंपरिक रूप से मानवता के व्यापक हित के लिए अपने सबसे प्रिय ज्ञान और बुद्धिमत्ता को हमेशा साझा करना चाहता है। यह प्रशिक्षण उसी भावना के साथ आयोजित किया गया है जिसमें हम एक-दूसरे से सीखने की आशा और अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में शासन की संघीय संरचना है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कल्याण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और अन्य आयोगों के अलावा 27 राज्य मानव अधिकार आयोग शामिल हैं। एनएचआरसी, भारत केवल मानव अधिकार समर्थन का मंच नहीं है बल्कि यह देश में मानव अधिकारों को लागू करने के लिए उतरदायी भी है।

इस अवसर पर एनएचआरसी, भारत और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। क्षमता निर्माण कार्यक्रम में मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर कई सत्र होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा।

***

PIB

NHRC, India's ITEC Executive capacity-building programme on human rights in partnership with the MEA for senior functionaries of NHRIs of Global South begins in New Delhi

Inaugurating it, NHRC, India Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian highlights India's rich diverse cultural ethos with various castes, communities, art forms and languages and shared values binding its unity for centuries

Says, there can't be tailor-made solutions under international norms to addressing human rights problems in every country having its own diverse socio-economic and cultural realities

Platforms like ITEC provide an opportunity to share and exchange each other's rich cultural diversity and human rights values, to think and find ways on how best to address the ever-emerging human rights challenges

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2107759

Posted On: 03 MAR 2025 4:01PM by PIB Delhi

The six-day Indian Technical and Economic Cooperation Executive (ITEC) Capacity Building Programme on human rights for the NHRIs of Global South, being organized by the National Human Rights Commission (NHRC), India in partnership with the Union Ministry of External Affairs (MEA) began in New Delhi today. About 47 participants from the NHRIs of 14 countries of the Global South have confirmed their participation. These are Madagascar, Uganda, Samoa, Timor Leste, DR Congo, Togo, Mali, Nigeria, Egypt, Tanzania, Mauritius, Burundi, Turkmenistan, and Qatar.

Justice V. Ramasubramanian, Chairperson, NHRC, India in his inaugural address said that India is a country of rich diverse cultural ethos with various castes, communities, art forms and languages and yet it thrives in its unity of shared values and traditions for centuries. However, he said that diversity also comes with diverse problems requiring diverse solutions. Every country has its socio-cultural, political, and economic traditions and diversities may face challenges while addressing the human rights issues given their standardised approaches set to dealing with them following the Universal Declaration of Human Rights. Therefore, solutions to the problems can't be tailor-made for every country to follow.

Justice Ramasubramanian said that such platforms like ITEC provide an opportunity to share and exchange each other's rich cultural diversity and human rights values to think and find ways how best to address the ever-emerging human rights challenges in each country with its social, cultural, political and economic realities.

He expressed his gratitude to the participating senior functionaries of the NHRIs of Global South and their countries for accepting NHRC, India's invitation to depute them for participation. He also referred to many ancient Indian texts highlighting the human values and ethos practiced in the countries or centuries, which hold relevance even today for the whole world.

Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi, Member, NHRC, India in his remarks stated that the Commission has played a crucial role in shaping India's human landscape through its wide-ranging initiatives. Unlike many Western approaches that emphasise individual freedom above all else, India follows a more balanced model that values both individual and collective rights. India's engagement in international human rights forums reflects its dedication to building a just and equitable global order. He said that capacity-building initiatives like ITEC play a crucial role in expanding our knowledge and refining our skills. While engaging in this programme, let us recognise the need to contextualise human rights principles within our national realities while remaining steadfast in our commitment to universal values of dignity, justice and equality.

Smt Vijaya Bharathi Sayani, Member, NHRC, India said that by sharing our collective wisdom and resources, we can significantly enhance the protection and promotion of human rights across our nations and regions in the scenario of constantly evolving global human rights landscape. She also highlighted some of the key thematic issues of human rights that are being focused on by the NHRC, India, including the rights of women and achieving gender equality, protecting marginalised communities, safeguarding vulnerable populations in the context of development and displacement, among others.

NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal in his opening remarks said that India traditionally always wants to share its most cherished knowledge and wisdom for the larger cause of humanity. This training has been organised with the same spirit wherein we hope and expect to learn from each other. He said that India has a federal structure of governance with 27 State Human Rights Commissions besides the National Human Rights Commission and other Commissions to address the issues of the rights and welfare of various segments of society. The NHRC, India is not just a human rights advocacy forum but responsible for enforcing human rights in the country.

On the occasion, senior officers of the NHRC, India and MEA were present. The capacity building programme has several sessions on various aspects of human rights to be addressed by the eminent expert speakers with a national and international perspective.

***

NSK

(Release ID: 2107759) Visitor Counter : 390

Observer Voice

India Hosts Global Human Rights Capacity Building Program

https://observervoice.com/india-hosts-global-human-rights-capacity-building-program-100071/

Shalini Singh | March 3, 2025 Last Updated: March 3, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC) of India, in partnership with the Union Ministry of External Affairs (MEA), is set to launch a six-day Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Executive Capacity Building Programme. Scheduled from March 3 to March 8, 2025, in New Delhi, this initiative will gather 47 senior officials from National Human Rights Institutions (NHRIs) across 14 countries in the Global South. The program aims to enhance human rights awareness and strengthen international cooperation.

Participants from Diverse Nations

The upcoming program will welcome representatives from a diverse group of 14 countries, including Madagascar, Uganda, Samoa, Timor Leste, the Democratic Republic of Congo, Togo, Mali, Nigeria, Egypt, Tanzania, Mauritius, Burundi, Turkmenistan, and Qatar. This initiative is tailored to meet the specific needs of the participating NHRIs, based on prior feedback. The NHRC has engaged eminent experts in the field of human rights to serve as resource persons, ensuring that participants receive high-quality training and insights.

Objectives and Expected Outcomes

The primary goal of the program is to provide participants with a comprehensive understanding of various dimensions of human rights and international perspectives. By sharing NHRC India’s experiences over the past three decades, the program aims to enhance awareness and knowledge among the NHRIs. Key outcomes include improved understanding of international human rights frameworks, insights into NHRC India’s best practices, and strengthened networking opportunities among NHRIs. The initiative also seeks to foster collaborations and partnerships at both regional and international levels, ultimately enhancing the capacity of participants to promote and protect human rights.

Engaging Learning Experience

Participants will engage in a variety of learning activities, including lectures and interactive sessions led by distinguished experts and practitioners in the field of human rights. The program will also feature cultural immersion experiences and field visits, providing a well-rounded understanding of human rights issues. This initiative is part of NHRC’s ongoing outreach efforts to promote a deeper understanding of human rights and build capacity among senior officials of NHRIs, ensuring they are better equipped to address human rights challenges in their respective countries.

Observer Voice

India Launches Human Rights Capacity Building Program

https://observervoice.com/india-launches-human-rights-capacity-building-program-100314/

Shalini Singh | March 3, 2025Last Updated: March 3, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC) of India, in collaboration with the Union Ministry of External Affairs, has inaugurated a six-day Capacity Building Programme focused on human rights for National Human Rights Institutions (NHRIs) from the Global South. The event, which commenced today in New Delhi, has attracted 47 participants from 14 countries, including Madagascar, Uganda, and Nigeria, among others. This initiative aims to foster dialogue and share best practices in addressing human rights challenges across diverse cultural contexts.

Inaugural Address Highlights Cultural Diversity

Justice V. Ramasubramanian, Chairperson of NHRC, delivered the inaugural address, emphasizing India's rich cultural diversity and the unique challenges it presents in addressing human rights issues. He noted that while the Universal Declaration of Human Rights provides a framework, each country must navigate its socio-cultural, political, and economic realities. Justice Ramasubramanian stressed that solutions cannot be one-size-fits-all, urging participants to explore tailored approaches that respect local contexts while adhering to universal human rights standards.

He expressed gratitude to the senior officials from the NHRIs of the Global South for their participation, highlighting the importance of sharing cultural values and human rights practices. This exchange, he believes, is crucial for developing effective strategies to tackle emerging human rights challenges.

Contextualizing Human Rights Principles

Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi, a member of NHRC, underscored the Commission's pivotal role in shaping India's human rights landscape through various initiatives. He contrasted India's balanced approach to human rights, which values both individual and collective rights, with Western models that prioritize individual freedoms. Dr. Sarangi emphasized the importance of contextualizing human rights principles within national realities while remaining committed to universal values of dignity, justice, and equality.

He encouraged participants to leverage the ITEC program to enhance their knowledge and skills, reinforcing the need for a nuanced understanding of human rights that reflects the complexities of each nation's circumstances.

Focus on Key Human Rights Issues

Smt. Vijaya Bharathi Sayani, another member of NHRC, highlighted the significance of collective wisdom in enhancing human rights protection across nations. She pointed out

that the NHRC is focusing on critical thematic issues, including women's rights, gender equality, and the protection of marginalized communities. Sayani emphasized the need to adapt to the evolving global human rights landscape, advocating for collaborative efforts to safeguard vulnerable populations amidst development and displacement challenges.

Shri Bharat Lal, Secretary General of NHRC, reiterated India's commitment to sharing its knowledge and wisdom for the greater good. He noted that the NHRC operates within a federal structure, comprising 27 State Human Rights Commissions, and is dedicated to enforcing human rights across various societal segments. The program aims to facilitate learning and exchange among participants, fostering a deeper understanding of human rights enforcement.

Program Structure and Expert Contributions

The capacity-building program will feature multiple sessions led by eminent experts, addressing various aspects of human rights from both national and international perspectives. Senior officials from NHRC and the Ministry of External Affairs were present at the inauguration, reflecting the collaborative spirit of this initiative. The program is designed to equip participants with the tools and knowledge necessary to address human rights challenges effectively within their respective countries.

As the program unfolds, it promises to be a significant platform for dialogue and learning, contributing to the global discourse on human rights and fostering a more equitable world.

Statesman

Six-day capacity building programme for rights bodies of Global South begins in Delhi

The Indian Technical and Economic Cooperation Executive (ITEC) capacity building programme for the National Human Rights Institutions (NHRIs) from Global South got underway here on Monday.

https://www.thestatesman.com/india/six-day-capacity-building-programme-for-rights-bodies-of-global-south-begins-in-delhi-1503403999.html

Statesman News Service | New Delhi | March 3, 2025 5:48 pm

The Indian Technical and Economic Cooperation Executive (ITEC) capacity building programme for the National Human Rights Institutions (NHRIs) from Global South got underway here on Monday.

The six-day programme is being organised by the National Human Rights Commission (NHRC) in collaboration with the Ministry of External Affairs (MEA).

The programme is being attended by 47 delegates from the NHRIs of 14 countries from the Global South. The participating countries include Madagascar, Uganda, Samoa, Timor Leste, DR Congo, Togo, Mali, Nigeria, Egypt, Tanzania, Mauritius, Burundi, Turkmenistan, and Qatar, as per the NHRC.

In his inaugural address, NHRC Chairperson Justice V Ramasubramanian said India is a country of rich and diverse cultural ethos with various castes, communities, art forms, and languages, yet thrives in its unity of shared values and traditions for centuries.

However, he said diversity also comes with diverse problems requiring diverse solutions. “Every country has its socio-cultural, political, and economic traditions and diversities may face challenges while addressing the human rights issues given their standardised approaches set to dealing with them following the Universal Declaration of Human Rights. Therefore, solutions to the problems can’t be tailor-made for every country to follow,” the Chairperson said.

Ramasubramanian also referred to many ancient Indian texts highlighting the human values and ethos practiced in the countries or centuries, which hold relevance even today for the whole world.

He expressed his gratitude to the participating senior functionaries of the NHRIs of Global South and their countries for accepting NHRC’s invitation to depute them for participation.

A NHRC member. Justice Bidyut Ranjan Sarangi, said the commission has played a crucial role in shaping India’s human landscape through its wide-ranging initiatives. “Unlike many Western approaches that emphasise individual freedom above all else, India follows a more balanced model that values both individual and collective rights.

India’s engagement in international human rights forums reflects its dedication to building a just and equitable global order,” Sarangi elaborated.

He said that capacity-building initiatives like ITEC play a crucial role in expanding our knowledge and refining our skills.

Vijaya Bharathi Sayani, who is also a member of the rights body, said by sharing our collective wisdom and resources, we can significantly enhance the protection and promotion of human rights across our nations and regions in the scenario of constantly evolving global human rights landscape.

She also highlighted some of the key thematic issues of human rights that are being focused on by the NHRC including the rights of women and achieving gender equality, protecting marginalised communities, safeguarding vulnerable populations in the context of development and displacement, among others.

NHRC Secretary General Bharat Lal said India traditionally wanted to share its most cherished knowledge and wisdom for the larger cause of humanity. This training has been organised with the same spirit wherein we hope and expect to learn from each other.

Senior officers of the NHRC and the MEA were present on the occasion.

Devdiscourse

ITEC Capacity Building Programme on Human Rights for Global South NHRIs Begins

Justice V. Ramasubramanian, Chairperson of NHRC, India, inaugurated the event by highlighting India's rich and diverse cultural heritage.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3284017-itec-capacity-building-programme-on-human-rights-for-global-south-nhris-begins

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 03-03-2025 21:53 IST | Created: 03-03-2025 21:53 IST

The six-day Indian Technical and Economic Cooperation Executive (ITEC) Capacity Building Programme on human rights, organized by the National Human Rights Commission (NHRC), India in collaboration with the Union Ministry of External Affairs (MEA), commenced today in New Delhi. The programme has drawn participation from 47 representatives of National Human Rights Institutions (NHRIs) across 14 countries from the Global South, including Madagascar, Uganda, Samoa, Timor Leste, DR Congo, Togo, Mali, Nigeria, Egypt, Tanzania, Mauritius, Burundi, Turkmenistan, and Qatar.

Justice V. Ramasubramanian, Chairperson of NHRC, India, inaugurated the event by highlighting India's rich and diverse cultural heritage. He acknowledged that while India thrives in unity despite its diverse communities, traditions, and languages, this diversity also presents challenges in human rights implementation. He emphasized that every nation faces unique socio-cultural, political, and economic challenges, making it difficult to apply uniform solutions to human rights issues based on the Universal Declaration of Human Rights. Instead, he advocated for a contextualized approach tailored to each country's realities.

Justice Ramasubramanian underscored the importance of platforms like ITEC, which provide a valuable opportunity for nations to exchange experiences and best practices in human rights protection. He expressed gratitude to all the participating NHRIs for accepting NHRC, India's invitation to collaborate and share knowledge. He also referenced ancient Indian texts that have long upheld human values and ethical governance, asserting their relevance in contemporary global human rights discussions.

Insights from NHRC Members

Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi, NHRC Member, highlighted the Commission's pivotal role in shaping India's human rights framework. He noted that India adopts a balanced approach to human rights, valuing both individual and collective rights, in contrast to many Western models that emphasize individual freedoms. He reiterated that India's engagement in international human rights forums reflects its dedication to fostering a just and equitable global order. He encouraged participants to leverage the training to develop

a nuanced understanding of human rights in alignment with national contexts while upholding universal values of dignity, justice, and equality.

Smt Vijaya Bharathi Sayani, another NHRC Member, emphasized the significance of collaborative efforts in enhancing human rights protection. She highlighted key thematic areas of NHRC, India's focus, such as promoting gender equality, protecting marginalized communities, and safeguarding vulnerable populations affected by development and displacement. She stressed that through shared wisdom and collective action, participating nations could reinforce human rights protections across their respective regions.

NHRC Secretary General's Opening Remarks

Shri Bharat Lal, NHRC, India's Secretary General, reiterated India's longstanding tradition of sharing knowledge and wisdom for the betterment of humanity. He stated that the training programme embodies this spirit of cooperation, providing an avenue for mutual learning. He also elaborated on India's federal structure in human rights governance, which includes 27 State Human Rights Commissions alongside the NHRC and other regulatory bodies working to uphold the rights and welfare of diverse societal segments. He emphasized that NHRC, India, not only functions as an advocacy body but also plays an active role in enforcing human rights protections.

Programme Structure and Expert Sessions

The capacity-building programme features multiple sessions led by distinguished national and international human rights experts. These sessions will cover a wide range of human rights aspects, fostering dialogue and sharing of best practices to address contemporary challenges effectively.

Senior officials from NHRC, India, and MEA were present at the event's inauguration, reaffirming India's commitment to strengthening human rights institutions and fostering global cooperation in this critical domain.

Insamachar.com

NHRI के लिए मानवाधिकारों पर छह दिवसीय भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी (ITEC) क्षमता निर्माण कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ

https://insamachar.com/the-six-day-indian-technical-and-economic-cooperation-executive-itec-capacity-building-programme-on-human-rights-for-nhris-began-in-new-delhi-today/

Editor Posted on | 3 मार्च 2025

वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान (एनएचआरआई) के लिए मानवाधिकारों पर छह दिवसीय भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी (आईटीईसी) क्षमता निर्माण कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसका आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। वैश्विक दक्षिण के 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के लगभग 47 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लेने के बारे में समहति व्यक्त की है। मेडागास्कर, युगांडा, समोआ, तिमोर लेस्ते, डीआर कांगो, टोगो, माली, नाइजीरिया, मिस्र, तंजानिया, मॉरीशस, बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान और कतर इन देशों में शामिल हैं।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत विभिन्न जातियों, समुदायों, कला रूपों और भाषाओं के साथ समृद्ध विविध सांस्कृतिक लोकाचार का देश है और फिर भी यह सदियों से साझा मूल्यों और परंपराओं की एकता में पनप रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विविधता के साथ विविध समस्याएं भी आती हैं, जिनके लिए विविध समाधानों की आवश्यकता होती है। हर देश की अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परंपराएं होती हैं और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद उनके मानकीकृत तरीकों को देखते हुए मानवाधिकार संबंधी मुद्दों का समाधान करते समय विविधताओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, समस्याओं का समाधान हर देश के लिए अलग-अलग नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा कि आईटीईसी जैसे मंच एक-दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और मानवाधिकार मूल्यों को साझा करने और आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि प्रत्येक देश में अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के साथ उभरती मानवाधिकार चुनौतियों का सर्वोत्तम तरीके से समाधान करने के तरीकों पर विचार और खोज की जा सके।

उन्होंने वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान और उनके देशों के भाग लेने वाले वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने एनएचआरसी, भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का भी नाम लिया, जो देशों या सदियों में प्रचलित मानवीय मूल्यों और लोकाचारों पर प्रकाश डालते हैं और आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी ने अपने भाषण में कहा कि आयोग ने अपनी व्यापक पहलों के माध्यम से भारत के मानवीय परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई पश्चिमी देशों के दृष्टिकोणों के विपरीत, जो हर चीज से ऊपर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, भारत एक अधिक संतुलित मॉडल का पालन करता है जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों अधिकारों को

महत्व देता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों में भारत की भागीदारी एक न्यायसंगत तथा समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए उसके समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आईटीईसी जैसी क्षमता निर्माण पहल हमारे ज्ञान के विस्तार और हमारे कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए, आइए हम सम्मान, न्याय और समानता के सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहकर, अपनी राष्ट्रीय वास्तविकताओं के भीतर मानवाधिकार के सिद्धांतों को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता को चिन्हित करें।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य विजया भारती सयानी ने कहा कि अपने सामूहिक ज्ञान और संसाधनों को साझा करके, हम लगातार विकसित हो रहे वैश्विक मानवाधिकार के परिदृश्य में अपने राष्ट्रों और क्षेत्रों में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मानवाधिकारों के कुछ प्रमुख विषयगत मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिन पर एनएचआरसी, भारत द्वारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के अधिकार और महिला-पुरुष आधारित समानता कायम करना, हाशिए वाले समुदायों की सुरक्षा, विकास और विस्थापन के संदर्भ में कमजोर आबादी की सुरक्षा आदि शामिल हैं।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत पारंपरिक रूप से मानवता के व्यापक हित के लिए अपने सबसे प्रिय ज्ञान और बुद्धिमत्ता को हमेशा साझा करना चाहता है। यह प्रशिक्षण उसी भावना के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें हम एक-दूसरे से सीखने की उम्मीद और अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में शासन की संघीय संरचना है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कल्याण के मुद्दों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य आयोगों के अलावा विभिन्न राज्यों में 27 मानवाधिकार आयोग हैं। एनएचआरसी, भारत केवल एक मानवाधिकार वकालत मंच नहीं है, बल्कि देश में मानवाधिकारों को लागू करने के लिए उत्तरदायी भी है।

इस अवसर पर एनएचआरसी, भारत और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। क्षमता निर्माण कार्यक्रम में मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर कई सत्र होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा।

Lokraag.com

मानवाधिकारों पर छह दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ, शामिल हुए ग्लोबल साउथ के 14 देश

https://lokraag.com/trending-now/six-day-workshop-on-human-rights-inaugurated-14-countries-of-global-south-participated/

लोकेश नशीने | March 3, 2025

नई दिल्ली (हि.स.)। वैश्विक दक्षिण के देशों में मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ पदाधिकारियों में क्षमता निर्माण की छह दिवसीय कार्यशाला का आज यहां शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत) ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईईटीसी) के अन्तर्गत इसका आयोजन किया है। ग्लोबल साउथ के 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) से लगभग 47 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये देश मेडागास्कर, युगांडा, समोआ, तिमोर लेस्ते, डीआर कांगो, टोगो, माली, नाइजीरिया, मिस्र, तंजानिया, मॉरीशस, बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान और कतर हैं।

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम (अध्यक्ष, एनएचआरसी) ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत विभिन्न जातियों, समुदायों, कला रूपों और भाषाओं के साथ समृद्ध विविध सांस्कृतिक लोकाचार का देश है और यह सदियों से साझा मूल्यों और परंपराओं की एकता में पनप रहा है। हालांकि विविधता के साथ-साथ विविध समस्याएं भी आती हैं, जिनके लिए विविध समाधानों की आवश्यकता होती है। हर देश की अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परंपराएं होती हैं और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद उनके साथ निपटने के लिए निर्धारित मानकीकृत दृष्टिकोणों को देखते हुए, विविधताओं को संबोधित करते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा कि आईटीईसी जैसे मंच एक-दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और मानवाधिकार मूल्यों को साझा करने और आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि प्रत्येक देश में अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के साथ उभरती मानवाधिकार चुनौतियों का सर्वोत्तम तरीके से समाधान करने के तरीकों पर विचार और खोज की जा सके।

उन्होंने वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई और उनके देशों के भाग लेने वाले वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने एनएचआरसी, भारत द्वारा उन्हें भागीदारी के लिए नियुक्त करने के निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का भी उल्लेख किया, जो देशों या सदियों में प्रचलित मानवीय मूल्यों और लोकाचारों पर प्रकाश डालते हैं, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं।

न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी (सदस्य, एनएचआरसी, भारत) ने अपने भाषण में कहा कि आयोग ने अपनी व्यापक पहलों के माध्यम से भारत के मानव परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई पश्चिमी दृष्टिकोणों के विपरीत, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हर चीज से ऊपर रखते हैं, भारत एक अधिक संतुलित मॉडल का पालन करता है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों अधिकारों को महत्व देता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों में भारत की भागीदारी एक न्यायसंगत और समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य विजया भारती सयानी ने कहा कि अपने सामूहिक ज्ञान और संसाधनों को साझा करके हम लगातार विकसित हो रहे वैश्विक मानवाधिकार परिदृश्य के परिदृश्य में अपने राष्ट्रों और क्षेत्रों में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मानवाधिकारों के कुछ प्रमुख विषयगत मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिन पर एनएचआरसी, भारत द्वारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता प्राप्त करना, हाशिए पर पड़े समुदायों की सुरक्षा, विकास और विस्थापन के संदर्भ में कमजोर आबादी की सुरक्षा आदि शामिल हैं।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत पारंपरिक रूप से मानवता के व्यापक हित के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को हमेशा साझा करना चाहता है। यह प्रशिक्षण उसी भावना के साथ आयोजित किया गया है जिसमें हम एक-दूसरे से सीखने की उम्मीद और अपेक्षा करते हैं।

Hindusthan Samachar

मानवाधिकारों पर छह दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ, ग्लोबल साउथ के 14 देश हुए शामिल

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2025/3/3/NHRC-Six-days-program-Inaugurated-Global-South-14.php

नई दिल्ली, 3 मार्च (हि.स.)। वैश्विक दक्षिण के देशों में मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ पदाधिकारियों में क्षमता निर्माण की छह दिवसीय कार्यशाला का आज यहां शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत) ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईईटीसी) के अन्तर्गत इसका आयोजन किया है। ग्लोबल साउथ के 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) से लगभग 47 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये देश मेडागास्कर, युगांडा, समोआ, तिमोर लेस्ते, डीआर कांगो, टोगो, माली, नाइजीरिया, मिस्र, तंजानिया, मॉरीशस, बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान और कतर हैं।

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम (अध्यक्ष, एनएचआरसी) ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत विभिन्न जातियों, समुदायों, कला रूपों और भाषाओं के साथ समृद्ध विविध सांस्कृतिक लोकाचार का देश है और यह सदियों से साझा मूल्यों और परंपराओं की एकता में पनप रहा है। हालांकि विविधता के साथ-साथ विविध समस्याएं भी आती हैं, जिनके लिए विविध समाधानों की आवश्यकता होती है। हर देश की अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परंपराएं होती हैं और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद उनके साथ निपटने के लिए निर्धारित मानकीकृत दृष्टिकोणों को देखते हुए, विविधताओं को संबोधित करते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा कि आईटीईसी जैसे मंच एक-दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और मानवाधिकार मूल्यों को साझा करने और आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि प्रत्येक देश में अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के साथ उभरती मानवाधिकार चुनौतियों का सर्वोत्तम तरीके से समाधान करने के तरीकों पर विचार और खोज की जा सके।

उन्होंने वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई और उनके देशों के भाग लेने वाले वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने एनएचआरसी, भारत द्वारा उन्हें भागीदारी के लिए नियुक्त करने के निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का भी उल्लेख किया, जो देशों या सदियों में प्रचलित मानवीय मूल्यों और लोकाचारों पर प्रकाश डालते हैं, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं।

न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी (सदस्य, एनएचआरसी, भारत) ने अपने भाषण में कहा कि आयोग ने अपनी व्यापक पहलों के माध्यम से भारत के मानव परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई पश्चिमी दृष्टिकोणों के विपरीत, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हर चीज से ऊपर रखते हैं, भारत एक अधिक संतुलित मॉडल का पालन करता है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों अधिकारों को महत्व देता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों में भारत की भागीदारी एक न्यायसंगत और समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य विजया भारती सयानी ने कहा कि अपने सामूहिक ज्ञान और संसाधनों को साझा करके हम लगातार विकसित हो रहे वैश्विक मानवाधिकार परिदृश्य के परिदृश्य में अपने राष्ट्रों और क्षेत्रों में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मानवाधिकारों

के कुछ प्रमुख विषयगत मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिन पर एनएचआरसी, भारत द्वारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता प्राप्त करना, हाशिए पर पड़े समुदायों की सुरक्षा, विकास और विस्थापन के संदर्भ में कमजोर आबादी की सुरक्षा आदि शामिल हैं।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत पारंपरिक रूप से मानवता के व्यापक हित के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को हमेशा साझा करना चाहता है। यह प्रशिक्षण उसी भावना के साथ आयोजित किया गया है जिसमें हम एक-दूसरे से सीखने की उम्मीद और अपेक्षा करते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / दधिबल यादव

The Statesman

NHRC seeks ATR from Odisha govt on scam in old-age pension

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Odisha government on the alleged disbursal of old-age pension social security scheme to ineligible beneficiaries in the Kendrapara and Jajpur districts.

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-seeks-atr-from-odisha-govt-on-scam-in-old-age-pension-1503404038.html

Statesman News Service | Bhubaneswar | March 3, 2025 7:09 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Odisha government on the alleged disbursal of old-age pension social security scheme to ineligible beneficiaries in the Kendrapara and Jajpur districts.

The apex rights panel, taking cognizance of a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy, asked the Principal Secretary of the Odisha government to looked into the allegations made in the complaint and submit an Action Taken Report (ATR) within four weeks for perusal of the Commission.

The complaint alleges that the welfare scheme related to the old-age pension has been grossly misused by the people with connections and influence in Odisha.

It further alleged that many people who were not old but taking advantage of their old age pension, especially in Kendrapara's Aul block and the Binjharpur block of Jajpur district, Odisha.

The complainant also alleged that without proper verification many youths in Odisha, below 60 years, are beneficiaries of the old age pension scheme whereas there are instances of worthy senior citizens still not covered under the old age pension scheme.

The commission seeks compliance of an Action Taken Report to be sent to the Commission within 4 weeks, an order stated on Monday.